an>

Title: Need to take steps to make minimum usage of papers.

श्री मजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब से इस लोक सभा में आया हुं उसके बाद और उसके पहले भी कई बार प्रकृति और पर्यावरण के सामने जिस तरह से चुनौतियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से खतरे बढ़ रहे हैं, उनके बारे में अनेक बार इस सदन में चर्चायें हयी हैं, विन्तन हुआ है और इस बार हमने संवेद स्वर में उसके बारे में विन्ता व्यक्त की हैं। हम सब लोग इस बात से विनितत हैं कि आने वाले पीढ़ी को हम किस तरह पूकृति को विकृत किये बगैर उन्हें ट्रान्सफर कर सकें, आगे हस्तांतरित कर सकें।

मैं जिस क्षेत् से आता हं, मेरे विद्यान सभा क्षेत्, लोक सभा क्षेत्र, में तीन सौ साल पहले 363 लोगों ने अमृता देवी विष्नोई नाम की महिला के नेतृत्व में अपनी श्रहादत, अपने जीवन की बिल पेड़ों की रक्षा के लिए दी थी<sub>।</sub> पेड़ों की कटाई कागज की खपत से सीधे जुड़ा हुआ विषय हैं<sub>।</sub> मैं जब से लोक सभा में आया हुं, आप सब पुराने लोग बैठे हुए हैं, आदरणीय वैंकैंच्या जी बैठे हुए हैं, सभापति महोदय बैठे हुए हैं और अनेक पुराने लोग बैठे हुए हैं। हमारे घर में सुबह जो भूरे रंग का लिफाफा आता हैं, इस सबकी आदत आप लोगों को पड़ी हुई होगी। लेकिन मैं जिस रिस्टिकोण से सोचता हूं, जिस तरह

इस लोक सभा में कागज की खपत होती हैं, जिस तरह सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की त्रैमासिक, छ' मासिक, बारह मासिक रिपोर्ट आती हैं, मैंने अनुमान लगाया है कि एक सांसद
को, एक टेन्योर में लगभग एक टन पेपर दिया जाता हैं। मैं इस सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्यों नहीं हम इक्कीसवीं सदी में इस तरह का कोई पूबंध करें, संकल्प
लें कि बढ़ते हुए कागज की खपत को कम करने के दृष्टिकोण से काम करें। हम एक नई शुरुआत करें कि अपने यहां किस तरह कम खपत कर सकते हैं। किस तरह सारी रिपोर्ट्स को आन लाइन
कर सकते हैं  यदि किसी मित्र को जरूरत है और वास्तव में उसे प्रिंटेड फार्मेट में चाहिए तो वह संदर्भित विभाग से आसानी से ले सकता है  हमें इस संबंध में इस समय कोई न कोई रेज़ोल्यूशन जरूर
पास करना चाहिए <sub>।</sub>
HON. DEPUTY-SPEAKER:
Kunwar Pushpendra Singh Chandel,

Shri Ramcharan Bohra and

Shri Devji M. Patel are permitted to associate with the issue raised by Shri Gajendra Singh Shekhawat.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, on this very important suggestion given by the hon. Member, the hon. Speaker has already initiated a discussion on that. We are consulting other political leaders in Parliament. We must evolve a broad consensus because this is a very important issue. When we are moving towards high technology, we should really accept this. I will try to pursue it with the Ministries, and also I would request the cooperation of all Members because the Speaker is already willing to consider it. Hon. Deputy-Speaker, Sir, you were also there that day. We will take it forward.

HON. DEPUTY-SPEAKER: We have already discussed this matter. There is consensus on this issue. However, at the same time, the issue of providing accommodation was also discussed. If we take both of them together, then only it will become easy. Otherwise, adopting that process in the existing system can be difficult.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We cannot do it in one stroke because there are legal problems as the court also needs documents. However, we can reduce the usage of paper and increase online usage.